AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ की सुराजी गांव योजना के अंर्तगत गरूवा योजना की भूमिका का अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
डॉ. तामेश्वरी साहू
सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग
बी. सी. एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
धमतरी, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। गांवों में निहित संसाधन एवं आधारभूत संरचना, कृषि एवं पूरक व्यवसाय पशुपालन को संबल प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में कुल 150 लाख पशुधन है, किंतु उचित प्रबंध एवं गुणवत्ता में अभाव के कारण पशुपालन घाटे का व्यवसाय सिद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए सुराजी गांव योजना अंतर्गत गरूवा (पशुधन) योजना आरंभ की गयी है। अध्ययन में पाया गया कि जिस गांव में मॉडल गौठान का निर्माण किया गया है, वहां गौठान योजना लाभप्रद है। किसान इस योजना से प्रसन्न है, किंतु अधिकांश गांवो में गौठान निर्माण अपर्याप्त संरचना के कारण योजना का लाभ अत्यंत सीमित है।

मुख्य शब्द

गरूवा, नरवा, धुरवा, गौठान, सुराजी गांव.

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 37.46 लाख कृषक परिवार है, जिसमें से 80 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक है। पशु संगणना 2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन 150.4 लाख है, जिसमें 98.13 लाख गौवंशीय, 13.9 लाख भैसवंशीय, 32.25 लाख भेड़ वंशीय, 4.39 सूअर एवं 0.036 अन्य पशुधन हैं। छत्तीसगढ़ की विशाल पशुधन का आर्थिक विकास में योगदान सीमित है। कृषि यंत्रीकरण के कारण भारवाहक पशुओं की उपयोगिता में कमी आयी है, देशी गायों में दुग्ध उत्पादकता निम्न होने के कारण किसानों में पशुपालन के प्रति रूझान में कमी आयी है, अतः किसान पशुपालन को घाटें का व्यवसाय मानने लगे है एवं आवारा पशुओं को खुला छोड़ देते है, जिससे फसलों की चराई एवं सड़क दुर्घटना एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं।

सुराजी गांव योजना का सामान्य परिचय

गांवों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'सुराजी गांव योजना' प्रारंभ की गयी है, जिसे नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके अंर्तगत चार योजना समाहित है, नरवा अर्थात् नाला, गरूवा अर्थात् पशुधन, घुरवा ग्रामीण क्षेत्र में कचड़ा निपटान के लिए बना गड्ढ़ा है एवं बारी का अर्थ है, घर के आसपास फल सब्जी उगाने का छोटा उद्यान। प्रस्तुत अध्ययन में गौ संवर्धन के उद्देश्य से संचालित गरूवा (पशुधन) योजना, की क्रियाशीलता एवं चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में गरूवा योजना की भूमिका का अध्ययन।
2. गरूवा योजना के क्रियान्वयन की चुनौती एवं संभावित समाधान का सुझाव।

अध्ययन की परिकल्पना

छत्तीसगढ़ में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन में गरूवा योजना सहायक है।

अध्ययन की प्रविधि

प्राथमिक आंकडों का संग्रहण दुर्ग जिला के पाटन विकास खण्ड एवं धमतरी जिला के धमतरी विकास खण्ड एवं बालोद जिला के गुरूर विकासखण्ड के कुल 15 गांवों से प्राप्त की गयी है जिसके लिए गांवों के चरवाहो, ग्रामीण जन, स्वसहायता समूह के सदस्य, गौठान प्रबंधन समीति के सदस्यों एवं कार्यक्रम अधिकारियो से मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी है।

द्वितीयक आंकड़े–समाचार पत्र, पत्रिकाओं, शासकीय विभागों के वेबसाइट में उपलब्ध प्रकाशन एवं आंकड़ों पर आधारित है।

गरूवा योजना का उद्देश्य

पशुधन की सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता संवर्धन द्वारा पशुधन को उत्पादक बनाना।

गरूवा योजना के तहत प्रत्येक ग्राम में मवेशियों के लिए गौठान निर्माण का प्रावधान है, गौठान की संरचना इस प्रकार हैः

1. **मवेशियों के बैठने के लिए प्लेटफार्मः** गौठान का निर्माण जल स्रोत के आसपास ऊंचाई वाले स्थान पर हो। 100 पशुओं के लिए एक एकड़ जमीन निर्धारित किया गया है। न्यूनतम तीन एकड़ क्षेत्रफल का भूखण्ड होना चाहिए। गिट्टी, रेत, मुरूम, मिट्टी से कच्ची निर्माण एवं गिट्टी सिमेंट द्वारा पक्का प्लेटफार्म निर्माण किया जाना है।
2. गौठान के चारों ओर का सीमांकन, दीवार या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन के अनुसार झाड़ियों या कांटे तार से किया जा सकता है।
3. गौठान के अंदर पशु शेड, चरवाहा कक्ष का निर्माण एवं छाया के लिए फलदार वृक्षारोपण किया जाना है।
4. पानी की निकासी व्यवस्था के साथ, चारे के लिए आसपास चारागाह, पैरा कटिंग मशीन एवं पानी टंकी निर्माण गौठान को पशु संरक्षण स्थल डेकेयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है।
5. गौठान से निकलने वाले अपशिश्ट पदार्थों से वर्मी कम्पोष्ट खाद निर्माण, सामुदायिक आधार पर गोबर गैस प्लांट की स्थापना एवं गौठान समीति द्वारा खाद एवं उर्जा के विक्रय द्वारा आय अर्जित करना।
6. गौठान में दुःध संग्रहण केंद्र की स्थापना, पशुधन में नस्लसुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, टीकाकरण एव बंधियाकरण की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे दूधारू पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुःग्ध उत्पादन में वृद्धि हो।

गौठान के प्रबंधन के लिए ग्राम गौठान समिति बनाया गया है, जिसके सदस्य ग्राम के सरपंच एवं गांव के प्रमुख नागरिक होते हैं।

गौठान योजना का चरणबद्ध क्रियान्वयन

प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 15 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में 1446 गौठान का निर्माण किया गया जिसमे में 21 ग्राम पंचायत में मॉडल गौठान तथा 97 गांवों में गौठान का निर्माण किया गया। गौठान में चरवाहों की नियुक्ति की गयी है। गोबर गैस प्लांट, वर्मी कम्पोष्ट खाद निर्माण के लिए महिला स्वसहायता समूहो एवं किसानों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया। इससे प्रत्येक गांव में 10–15 परिवारों को स्वरोजगार के अवसर

प्राप्त होंगे, आवारा मवेशियों की समस्या में कमी आएगी। वन विभाग एवं कृषि विभाग को वृक्षारोपण, सेरिकल्चर एवं फ्लोरिकल्चर जैसे गतिविधियों को चलाने की संबद्ध किया गया है। ''छत्तीसगढ़ की 80 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, नरूवा गरवा घुरवा योजना गांवों की छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने मं अत्यंत सहायक है। जैविक कृषि की आवश्यकता को पूरा करने में घुरवा योजना कारगर सिद्व हो सकता है" (Mahule B. et al. 2023). ''नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भूजल रिचार्ज, सिंचाई की उपलब्धता एवं जैविक कृषि में सहायता प्राप्त हो रही है साथ ही किसानों को दोहरी फसलें लेने में आसानी हो रही है। इसके तहत पशुओं की उचित देख–रेख संभव है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी तथा पोषण स्तर में सुधार होगा। यह अत्यंत ही महत्त्वाकांक्षी एवं चहुँमुखी की योजना है, जिसकी चर्चा देश के बाहर भी हो रही है। इस योजना का विस्तार भविष्य में भी लाभदायक सिद्ध होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार संपूर्ण प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएगी।" (Gupta A. 2023)

राज्य स्तर पर गरूवा योजना कार्यकारी समीति में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, जल संसाधन, उर्जा विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय एवं कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित विशय विशेषज्ञ सम्मिलित है। जिला स्तरीय कार्यकारी समीतियां में जिलाधीश अध्यक्ष है, समीति में वन मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, कृषि सह परियोजना प्रबंधक, क्रेडा के अभियंता भूअभिलेख अधिकारी एवं दो निर्वाचित जन प्रतिनिधि सम्मिलित है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अनुसार ''कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने स्थानीय संसाधनों को विकसित करने एवं व्यापक तौर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।'' मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा के अनुसार– ''इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की कई समस्याओं का व्यावहारिक हल निकल सकता है। साउथ एशिया पेस्टोरल एलायंस के कन्वेनर अनु वर्मा के अनुसार ''भारत में इस प्रकार की योजना तो सुनने में अच्छी लगती है, ईमानदारी से अमल न हो तो फिर कुछ अर्थ नहीं निकलता है''। समस्त कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश में संचालित है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवेश के व्यापक विकास की परिकल्पना की गयी है।

धमतरी जिले में योजना का क्रियान्वयन

प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण धमतरी जिले के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुधन है। गौठान योजना के प्रथम चरण में धमतरी जिले में 57 गांवों में समुचित सुविधा युक्त गौठान निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए रूरबन मिशल एवं मनरेगा मद से 4 करोड 1 लाख 98 हजार एवं रूरबन मिशन से 2 करोड़ 97 लाख 46 हजार और गौण खनिज से 6 करोड़ 4 लाख रू. खर्च का प्रावधान है।

1. ग्राम लोहरसी, परसतराई, पोटियाडीह एवं खरतुली में गौठान मिटटी मुरूम से बने है। उचित ढलान के अभाव में वर्शाकाल में कीचड एवं दलदल की समस्या होती है, कांटेतार से गौठान की घेराबंदी की गयी है। गौठान में गोबर से जैविक खाद बनाने का कार्य स्वसहायता समूह की महिलाएं करती है। जैविक खाद को 8 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर पर विक्रय करती हैं, जिससे ग्रामवासी अपने खेतों में जैविक खाद का प्रयोग कर रहे है, यहां के निवासियों ने यह माना कि गौठान में पैरा एवं घास की कमी है, यहां कुछ किसान पैरादान कर रहे है, किंतु इसके भण्डारण व्यवस्था का अभाव है। किसानों ने माना कि आवारा पशुओं की समस्या में कमी आयी है।
2. देवगांव में आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है, जिसके तहत पेयजल के लिए सोलर पंप एवं पानी टंकी, पशुओं के लिए कोटना एवं अन्य आवश्यक संरचना का निर्माण किया गया है, किंतु गौठान मिटटी मुरूम से बनाने के कारण वर्षाकाल में कीचड़ की समस्या होती है।
3. ग्राम भोइना के गौठान स्थल सीमेंट से बना है, किंतु सुरक्षा घेरा एवं चारे पानी का अभाव है, चरवाहों के लिए छाया की व्यवस्था भी नहीं है।

4. ग्राम संबलपुर के ग्रामीणों ने माना कि गौठान योजना के कारण पशुओं के अन्यत्र घूमने फसलों की चराई की समस्या से निजात मिली है। चरवाहे प्रसन्न है, किंतु ग्रामीणों का कहना है, कि चरवाहे आलसी हो गये है। पशुओं को गौठान में बंद करके लंबे समय के लिए घर चले जाते है, या अन्य गांव चले जाते है।
5. ग्राम सेहरा डबरी में गौठान निर्माण के लिए पेंड़ों की कटाई की गयी है, जिससे पर्यावरण का ह्रास हुआ है, गौठान निर्माण में आधारभूत संरचना एवं जल प्रबंधन का अभाव है, बारिश में कीचड़ भर जाता है।

ग्राम दुगली एवं कंडेल के ग्रामवासियों ने स्व प्ररित होकर निजी लागत से गौठान का निर्माण किया है जो एक प्रशंसनीय पहल है।

जिला बालोद के ग्राम डढ़ारी का मॉडल गौठान

ग्राम डढ़ारी में आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है। यहां गौठान प्लेटफार्म सीमेंट से बना है, गौठान में स्वच्छता है। पशुओं के लिए चारे एवं पानी की उत्तम व्यवस्था है, सोलर ऊर्जी मोटर पंप से जलापूर्ति होती है। स्व–सहायता समूह की महिलाएं गौठान में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण करती है। किसान और चरवाहे दोनों इस योजना से प्रसन्न है। डढ़ारी के किसानों ने माना कि मॉडल गौठान के बनने से खेतो में चरी की समस्या में कमी आई है तथा ग्राम स्वच्छता में भी वृद्धि हुई है।

दुर्ग जिले में गौठान योजना का क्रियान्वयन

दुर्ग जिले के ग्राम चेटवा, मुरमुन्दा, पेण्ड्रीतराई, दारगांव ढ़ाबा घुघसीड़ीह, सांकरा, अमलीडीह, पांहदा अ, जामगांव एम, ढ़ौर आदि गांवों में मॉडल गौठान का निर्माण किया गया है सभी गौठानों में कांटेतार से सीमांकन किया गया है। चारागाह व पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। यहां पशु अपशिष्ट पदार्थ से वर्मी कम्पोष्ट खाद बनाने का कार्य स्वसहायता समूह की महिलाएं करती है। जल सुविधा के लिए सौर उर्जा वाले मोटर पंप लगे हुए है। इन गौठानों को देखने से एक अभिनव पहल की छवि दृष्टिगोचर होती है।

दुर्ग जिले के ग्राम घुघसीड़ीह का मॉडल गौठान

मॉडल गौठान की तरह अन्य गांवों में सुविधाएं नहीं है। अधिकांश गांवों में गौठान योजना के तहत गौठान स्थल मिट्टी, मुरूम से बना है। कांटा तार से सीमांकन किया गया है, जहां चारा एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधा का अभाव है। पाटन तहसील के ग्राम आगेसरा, उमरपोटी, गातापार किकिरमेटा एवं बटरेल में गौठान का सुरक्षा घेरा केवल तार कांटे से किया गया है। यहां के किसानों का कहना है, कि इस योजना से उन्हे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। उनका मानना है, कि गौठान की घेराबंदी दीवार से होनी चाहिए, गोबर से खाद बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा गौठान में सुरक्षित वृक्षारोपन हो जिससे पशुओं की गर्मी एवं धूप से सुरक्षा हो सके। गौठान में अपर्याप्त संरचना के कारण यहां के किसान असंतुष्ट है।

गौठान योजना की चुनौतियां

प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया सभी गांवों में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ सामान्य चुनौतियां हैः

1. गौठान के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव व नियमित रूप से चारा एवं पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वृहद् मात्रा में वित्त की आवश्यकता है। वित्तीय व्यवस्था के साथ सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता है किंतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की कमजोर इच्छा शक्ति बहुत बड़ी बाधा है।

2. किसानों का मानना है, कि पशुओं को एक ही स्थान पर दिन भर रखने से पशुओं के स्वास्थ्य एवं गतिशीलता में कमी आयेगी।

निष्कर्ष

गौठान योजना पशुधन संरक्षण एवं ग्रामीण विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना का राज्यव्यापी क्रियान्वयन नीतिगत आधार पर किया जा रहा है, किंतु वर्तमान में अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है। गरूवा योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशासन एवं जन समुदाय का समन्वित सतत प्रयास आवश्यक है।

सुझाव

योजना की सार्थकता के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है इसके साथ ही प्रशासन की दृढ़ इच्छा शक्ति वांछनीय है। गौठान की आधारभूत संरचना का निर्माण पक्का एवं मजबूत होना चाहिए। योजना में निर्धारित संरचना का निर्माण सभी गांव की गौठानों में होना चाहिए। पशुओं की गर्मी एवं धूप से सुरक्षा के लिए पर्याप्त वृक्षारोपण किया जाए। पशुपालन व्यवसाय को लाभदायक बनाने के लिए इससे प्राप्त उत्पादों जैसे दुःग्ध उत्पाद एवं जैविक खाद के लिए उत्तम विपणन प्रणाली होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, सुराजी गांव योजना, मार्गदर्शिका सुराजी गांव प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ शासन।
2. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में (2022) आर्थिक सांख्यिकीय, संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. त्रिपाठी, संजय एवं त्रिपाठी, चंदन (2012) *छत्तीसगढ़ वृहद् संदर्भ,* उपकार प्रकाशन, आगरा।
4. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका वर्ष 2013 जिला योजना सांख्यिकीय कार्यालय, धमतरी।
5. माडुले, भावना; चंद्राकर, प्रतिबाला; सोनी, निलेष (2023) छत्तीसगढ़ की विकास योजना नरवा, घुरवा बाड़ी के संदर्भ में ग्राम कातरों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, *International Journal of reviewsand research in social science (IJRRSS),* vol 11, Issue 02, p. 72-80.
6. गुप्ता, अरुणेश कुमार छत्तीसगढ़ (2021) राज्य की नरवा, गरुवा, घुरुवा और बाड़ी योजना, *Shodh Samagam,* ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (Print), April - June 2021, Volume 04, Issue 02, p.1604-17, Link https://shodhsamagam.com/uploads/issues_tbl/Chhattisgarh%20Rajya%20ki%20Narwa,%20Garuwa,%20Ghurwa%20our%20Baadi%20Yojana.pdf, Accessed on 10/09/2023.
7. जन संपर्क विभाग छत्तीसगढ़, 2012 पत्रिका – राहें विकास की।
8. downtoearth.org.in, Accessed on 11/02/2022.
9. www.naidunia.com, Accessed on 10/02/2022.
10. https//www.bhaskar.com>news, Accessed on 10/02/2022.
11. www.patrika.com, Accessed on 13/02/2022.
12. http//agriportal.cg.nic.in, Accessed on 22/02/2022.

——==00==——